International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 04(II), October - December, 2025, pp. 169-174

कौशल विकास एवं आय सृजनः झुंझुनू जिले के विशेष संदर्भ में

शेरसिंह[1*] | डॉ. श्वेता[2]

[1]पीएच.डी. शोधार्थी, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान।
[2]सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान।

[*]Corresponding Author: sschhapunia@gmail.com

Citation: शेरसिंह, & श्वेता. (2025). कौशल विकास एवं आय सृजनः झुंझुनू जिले के विशेष संदर्भ में. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 07(04(II)), 169–174.

सार

विश्व के बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में कौशल विकास का क्षेत्र व्यापक हो गया हैं। प्रत्येक देश अपनी आर्थिक नीति में कौशल विकास को महत्व दे रहा है। कौशल विकास पर विश्व में सबसे अधिक कार्य एशिया महाद्वीप के चीन में हुआ है। इसी कारण से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी उसकी आर्थिक वृद्धि की दर 8 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्श आंकी गई है। इसी वजह से चीन एक विकसित, आर्थिक शक्ति सम्पन देश कहलाता है। भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य देश, जिसकी अधिकांश जनसंख्या का भाग युवा है जिसमें अनेक क्षमतायें विद्यमान हैं। इस क्षमता का उपयुक्त तरीके से उपयोग करने तथा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए कौशल विकास की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कौशल विकास से व्यक्ति की उद्यमिता का विकास होता है, जिससे नये रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनायें बनाई गई हैं, जिनको विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया हैं। इनमें ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर शहरी रोजगार योजना तथा प्रसिद्व मनरेगा योजना प्रमुख हैं। ये योजनायें प्रभावशाली होते हुए भी इसका अपेक्षित लाभ न तो लोगों को प्राप्त हो सका है और ना ही देश के विकास की गति इतनी बढ़ पायी है। इन योजनाओं के तभी सफल होने की सम्भावना है, जब लोगों की कार्यदक्षता में सुधार लाया जाता है। प्रस्तुत शोध में राजस्थान में कोशल विकाश से विभिन्न कोशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित युवाओं की आय में हुए परिवर्तन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

शब्दकोशः *कौशल विकास, आय सृजन, रोजगार, आर्थिक नीति, जनसंख्या।*

प्रस्तावना

जॉनसन एवं ब्राउन (2023) ने कनाडा में प्रवासी युवाओं की कौशल संबंधी चुनौतियों का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया। उनके शोध में यह स्पष्ट हुआ कि लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो स्थानीय भाषा, सांस्कृतिक संदर्भ और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप डिज़ाइन किए गए थे, प्रवासी समुदाय को श्रम बाज़ार में बेहतर ढंग से समाहित करने में प्रभावी सिद्ध हुए। अध्ययन में यह भी दर्शाया कि प्रशिक्षित प्रवासी युवाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार देखा गया। इसके अतिरिक्त, शोध से यह संकेत प्राप्त हुआ कि प्रवासी युवाओं के लिए दी जाने वाली कौशल प्रशिक्षण योजनाओं में निरंतर समर्थन, परामर्श और

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

पुनःप्रशिक्षण की व्यवस्था होना आवश्यक है, ताकि उनकी रोजगार क्षमता सतत् बनी रहे और वे सामाजिक, आर्थिक समावेशन में सक्रिय भागीदारी कर सकें।

रिचड्‌र्स एवं हॉल (2023) ने जर्मनी के "ड्युअल सिस्टम" की सफलता का विश्लेषण किया। उनके शोध में यह पाया गया कि शिक्षा और उद्योग के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से युवाओं को न केवल उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण मिला, बल्कि यह प्रणाली जर्मनी की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने में भी सहायक रही। अध्ययन में दर्शाया गया है कि इस मॉडल में विद्यालय और उद्योग के बीच स्थायी साझेदारी और वास्तविक कार्य अनुभव का समावेश युवाओं को रोजगार–योग्य बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि अन्य देशों के लिए इस मॉडल को अपनाने के लिए स्थानीय उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच मजबूत संवाद, पाठ्यक्रम अनुकूलन और उद्योग आधारित प्रशिक्षण का ढाँचा विकसित करना आवश्यक है।

वर्मा, कौशल (2024) ने बताया कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला है। यह समुदाय को सक्रिय एवं उत्पादन जन–शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा से जनशक्ति में मानवीय मूल्यों की स्थापना होती है। वैश्वीकरण के युग में प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है अतः जनशक्ति को आवश्यक कौशल से युक्त होना नितान्त ज़रूरी है। कौशल युक्त होने से उनकी उत्पादकता में वृद्धि होने से वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।

वर्तमान शिक्षा परंपरावादी है अतः इसमें कौशल युक्त पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना अति आवश्यक है। इससे शिक्षा एवं रोज़गार के मध्य के अंतराल को समाप्त किया जा सकेगा। कौशल विकास पाठ्यक्रमों को निर्मित करते समय यह आवश्यक है कि बदलते परिवेश को देखते हुए नवीनतम तकनीकों का इसमें समावेश किया जावे। इससे राज्य में सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं के निर्माण से रोज़गार सृजन आर्थिक उत्थान एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

चौधरी, अरविंद (2022) ने बताया कि देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ युवा श्रम शक्ति की संख्या तो अत्यधिक है, परंतु उनमें से अधिकांश के पास उद्योग जगत की माँग के अनुरूप कौशल नहीं है। अध्ययन में प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि कौशल विकास प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं में रोजगार की संभावना 40 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि बिना प्रशिक्षण वाले युवाओं को अस्थायी और असुरक्षित कार्यों में ही रोजगार मिल पाया। शोध में यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर कौशल नीतियों को "स्थानिक उद्योग–आधारित" दृष्टिकोण से तैयार किया जाए।

त्रिपाठी, अमिता (2021) ने अपने अध्ययन "महिला सशक्तिकरण और कौशल प्रशिक्षण" (Journal of Social Development) खंड–19 में ग्रामीण महिलाओं के बीच चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। अध्ययन में यह पाया गया कि जिन महिलाओं ने सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर, और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनकी घरेलू आय में औसतन 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं ने घरेलू आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भागीदारी दिखाई और बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर खर्च की प्रवृत्ति में भी सुधार देखा गया। त्रिपाठी ने यह निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण केवल प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव नहीं है; प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्थानीय रोजगार अवसरों और विपणन सहायता से प्रत्यक्ष संबंध होना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थानों और स्थानीय बाजार के बीच साझेदारी विकसित की जानी चाहिए, जिससे महिलाएँ अपने कौशल का उपयोग कर स्थायी स्वरोज़गार प्राप्त कर सकें और सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

शोध के उद्देश्य

- कौशल विकास से विभिन्न कौशल विकास पाठ्‌यक्रमों में प्रशिक्षित युवाओं में प्रशिक्षित युवाओं की आय में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
- रोजगार अवसरों में अभिवृद्धि हेतु सुझाव व नीति निदेशन करना।

परिकल्पना

- कौशल विकास से विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित युवाओं में प्रशिक्षित युवाओं की आय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में कौशल विकास का रोजगार सृजन में योगदान का अध्ययन करने हेतु राजस्थान राज्य का उद्देश्यपूर्वक चयन किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान राज्य 7 सम्भागों में विभक्त है। प्रस्तुत शोध हेतु हमने जयपुर सम्भाग का चयन उद्देश्यपूर्वक किया है क्योंकि जयपुर संभाग में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर अपनी आजीविका हेतु निर्भर है। कृषि रहित व्यवसायों का अभाव है। यद्यपि सेवा क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ है परन्तु कौशल के अभाव में लोगों की आय कम है। अतः सरकार द्वारा कौशल सृजन के उपायों एवं योजनाओं के प्रभावों का आंकलन तथा कौशल विकास के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु हमने जयपुर सम्भाग का चयन किया है।

जयपुर सम्भाग में पांच जिले यथा अलवर, जयपुर, दौसा, झुझुनू एवं सीकर है। प्रस्तुत शोध हेतु हमने झुझुनू जिले का चयन उद्देश्यपूर्वक किया है क्योंकि यह एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां रोजगार के अवसरों का अभाव है एवं लोग रोजगार की तलाश में प्रवासरत रहते है।

कौशल निर्माण की योजनाओं का रोजगार सृजन एवं राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव का आंकलन करने हेतु झुझुंनू जिले का चयन किया है। सूक्ष्म अध्ययन हेतु हमने झुझुंनू जिले की कुल 6 तहसीलों में से 3 तहसीलें यथा नवलगढ़, चिड़ावा एवं खेतड़ी का चयन यादृच्छिक रूप से किया है। प्रत्येक तहसील से हमने सरल यादृच्छिक पद्धति से 10 गांवों का चयन किया है जिससे कुल 30 गाँव चयनित हुए है।

प्रत्येक गांव में कौशल निर्माण से प्रभावित लोगों की सूची तैयार कर सरल यादृच्छिक पद्धति से हमने 10 उतरदाताओं का चयन किया है। इस प्रकार प्रतिदर्श आकार 30 x 10 = 300 लाभार्थी है।

प्रत्येक गांव से 10 उतरदाता अर्थात एक तहसील से 100 उतरदाता। प्रतिदर्श आकार 30 x 10 = 300

प्रस्तुत शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ो पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों की प्राप्ति स्वयं शोधकर्ता द्वारा अनुसूची के माध्यम से प्राप्त की गई है, वहीं द्वितीयक आंकड़ो की प्राप्ति राजस्थान एवं भारत सरकार के विभिन्न प्रकाशनों, अखबारों पत्र पत्रिकाओं से की गई है। झुझुंनू की सूचनाएं जिला सांख्यिकी रूपरेखा एवं अन्य जिला स्तरीय प्रकाशनों से की गई है। संकलित आंकड़ो का विश्लेषण विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों जैसे औसत, प्रतिशत, सहसम्बन्ध, प्रतीपगमन आदि द्वारा किया गया है।

उत्तरदाताओं की आय पर कौशल विकास के प्रभाव का विश्लेषण

जन सामान्य के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु आय का स्तर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर न्यून होने के कारण लोगों की आय का स्तर कम होता है। क्योंकि लोग छोटे उद्योग–धन्धों में कार्यरत होते है अथवा कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं जहां उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग नही हो पाता है। अतः यदि इन क्षेत्रों में लोगों की कौशल क्षमता में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाएं तो उनकी आय के स्तर में वृद्धि होगी।

यहा। हमने कौशल विकास से उत्तरदाताओं की आय में हुए परिवर्तन को मापने का प्रयास किया है। इस हेतु हमने उत्तरदाताओं की कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति से पूर्व की आय तथा कौशल प्रशिक्षण के पश्चात् प्राप्त आय का विश्लेषण किया है। यह अग्र ताालिका में प्रस्तुत है –

तालिका 1: उत्तरदाताओं की आय पर कौशल विकास के प्रभाव का विश्लेषण कौशल प्रशिक्षण के पूर्व उत्तरदाताओं की आय का विवरण

तहसील	50 हजार से 1 लाख	1 से 1.5 लाख	1.5 से 2 लाख	2 से .5 लाख	2.5 लाख से अधिक	योग
नवलगढ	45	20	25	10	—	100
खेतडी	48	22	20	10	—	100
चिडावा	50	20	25	5	—	100
योग	143	62	70	25	—	300

स्त्रोतः क्षेत्रीय सर्वेक्षण

उत्तरदाताओं की आय पर कौशल विकास के प्रभाव का विश्लेषण

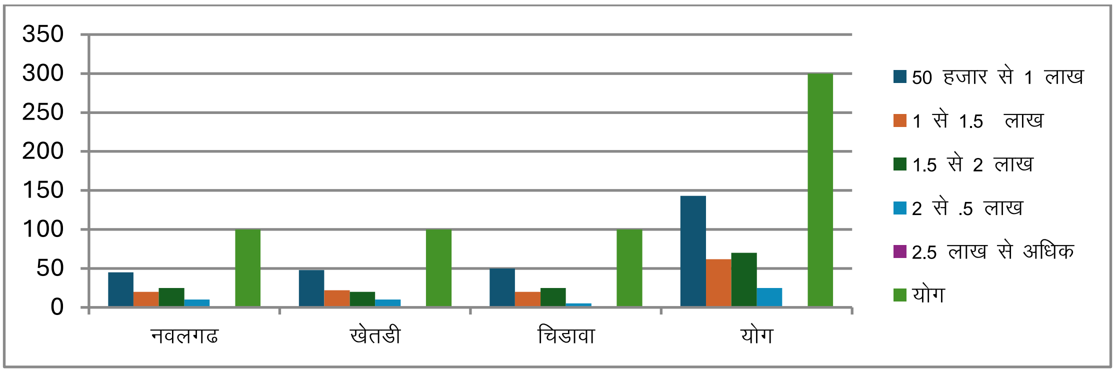

उपरोक्त तालिका एवं आरेख से स्पष्ट है कि नवलगढ में 45 प्रतिशत, खेतडी में 48 प्रतिशत एवं चिडावा में 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 50 हजार रू से 1 लाख रू के मध्य थी।

सारणी से स्पष्ट है कि नवलगढ एवं चिडावा के क्रमशः 20 प्रतिशत एवं खेतड़ी के 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 1 से 1.5 लाख रू के मध्य थी।

सारणी से विदित होता है कि नवलगढ एवं चिड़ावा में क्रमशः 25 प्रतिशत एवं खेतड़ी के 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूर्व वार्षिक आय 1.5 से 2 लाख रू के मध्य थी।

सारणी से स्पष्ट है कि नवलगढ़ एवं खेतड़ी के क्रमशः 10 प्रतिशत एवं चिड़ावा के 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 2 से 2.5 लाख रू के मध्य थी।

कुल 47.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कौशल प्रशिक्षण से पूर्व आय 50 हजार से 1 लाख रू. के मध्य थी। 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 1 से 1.5 लाख रू के मध्य थी। 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 1.5 लाख से 2 लाख रू के मध्य थी। वहीं शेष 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 2 से 2.5 लाख रू के मध्य थी।

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूर्व अधिकांश उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 50 हजार रू से 1 लाख रू के मध्य थी।

अग्र तालिका में यह जानकारी प्रस्तुत की गयी है कि उत्तरदाताओं द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उनकी वार्षिक आय कितनी है।

तालिका 2: कौशल प्रशिक्षण के पश्चात् उत्तरदाताओं की आय का विवरण

तहसील	1 से 2 लाख	2 से 3 लाख	3 से 4 लाख	4 से 5 लाख	5 लाख से अधिक	योग
नवलगढ	—	50	40	10	—	100
खेतडी	—	45	42	13	—	100
चिडावा	—	40	40	20	—	100
योग	—	135	122	43	—	300

स्त्रोतः क्षेत्रीय सर्वेक्षण

कौशल प्रशिक्षण के पश्चात् उत्तरदाताओं की आय का विवरण

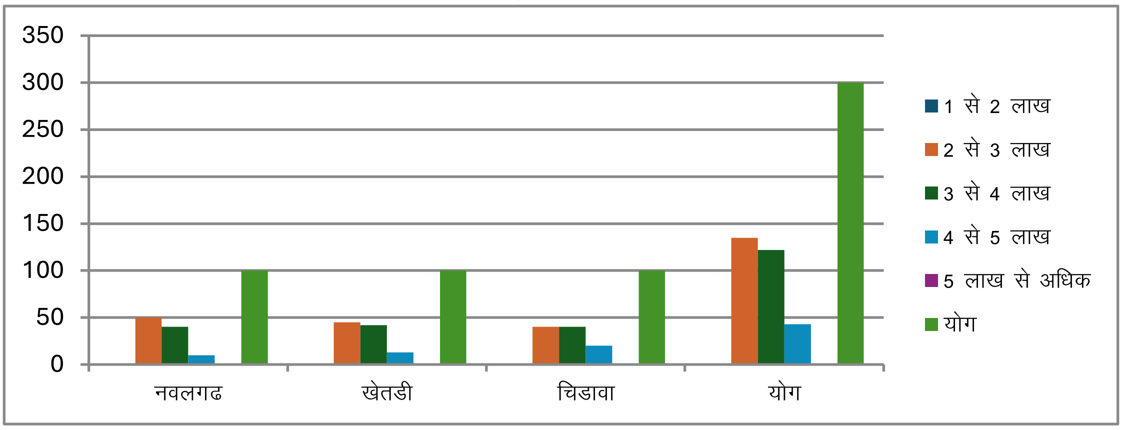

उपरोक्त तालिका एवं आरेख से स्पष्ट है कि नवलगढ के 50 प्रतिशत, खेतड़ी के 45 प्रतिशत एवं चिड़ावा के 40 प्रतिशत उत्तरदाता की कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् वार्षिक आय 2 से 3 लाख रू के मध्य थी।

इसी प्रकार नवलगढ़ के 40 प्रतिशत, खेतड़ी के 42 प्रतिशत एवं चिड़ावा के 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् वार्षिक आय 3 से 4 लाख रू के मध्य थी।

सारणी से स्पष्ट है कि नवलगढ के 10 प्रतिशत, खेतड़ी के 13 प्रतिशत एवं चिड़ावा के 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् वार्षिक आय 4 से 5 लाख रू के मध्य थी।

कुल 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् आय 2 से 3 लाख रू के मध्य थी, कुल 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् आय 3 से 4 लाख रू. के मध्य थी। इसी प्रकार शेष 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं की कौशल प्रशिक्षण के पश्चात् आय 4 से 5 लाख रू के मध्य थी।

निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उत्तरदाताओं की आय में वृद्धि होने से अधिकांश उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 2 से 4 लाख रू के मध्य थी।

कौशल प्रशिक्षण से उत्तरदाताओं की आय में वृद्धि की सार्थकता जांच

यहां हमने कौशल प्रशिक्षण से उत्तरदाताओं की आय में हुई वृद्धि की सार्थकता की जांच करने का प्रयास किया है। इस हेतु निम्न शुन्य परिकल्पना ली गयी है।

परिकल्पना परीक्षण

कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात् उत्तरदाताओं की आय में कोई सार्थक परिवर्तन नही हुआ है।

इस हेतु हमने स्टूडेण्ट के ज परीक्षण का प्रयोग किया है। ज परीक्षण के परिणाम निम्नवत है

तालिका 3: कौशल प्रशिक्षण से उत्तरदाताओं की आय में हुए परिवर्तन की सार्थकता जांच

मापदण्ड	कौशल प्रशिक्षण से पूर्व आय	कौशल प्रशिक्षण के पश्चात आय
उत्तरदाताओं की संख्या (n)	300	300
औसत वार्षिक आयः	72000	220000
मानक विचलन	28000	310000
t मुल्य		8.26
D.F.		598
P.मुल्य		0.0006
निष्कर्ष		शुल्य परिकल्पना अस्वीकृत

स्त्रोतः आगणित

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कौशल प्रशिक्षण से पूर्व उत्तरदाताओं की औसत वार्षिक आय 72000 रू थी, जो कौशल प्रशिक्षण के पश्चात् बढकर 220000 रू हो गयी है। इससे स्पष्ट है कि कौशल विकास कार्यक्रमों से लोगों की कार्यक्षमता एवं उत्पादता में वृद्धि होने से उनकी आय में वृद्धि हुई है।

यहां T परीक्षण का आंकलित मान 8.26 है जो 95 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर इसके सारणी मान 1.962 से अधिक है, अतः हमारी शुन्य परिकल्पना गलत सिद्ध होती है एवं यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कौशल विकास पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उत्तरदाताओं की आय में सार्थक रूप से वृद्धि हुई है।

सुझाव

- पाठ्यक्रम की वार्षिक समीक्षाः हर साल औद्योगिक विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो बाजार की जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम में बदलाव करे।
- ऑन–द–जॉब ट्रेनिंग (OJT) अनिवार्य होः प्रशिक्षण का कम से कम 40 से 50 प्रतिशत समय छात्रों को वास्तविक कार्यस्थल (फैक्ट्री या ऑफिस) में बिताना चाहिए। इससे उन्हें काम का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा ।
- भविष्य के कौशल पर ध्यानः राजस्थान की 'कौशल नीति 2025' के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेष कोर्स शुरू किए जाने चाहिए ।
- पशुपालन का आधुनिकीकरणः ग्रामीण युवाओं को वैज्ञानिक पशुपालन, दुग्ध शीतलन (Milk Cooling) और चारा प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर "श्वेत क्रांति" को बल दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जॉनसन, टी., एवं ब्राउन, पी. (2023). कनाडा में प्रवासी युवाओं की कौशल दृ संबंधी चुनौतियाँ और श्रम बाज़ार में उनका समावेशन. International Journal of Migration and Skills Development, 12(3), 45 – 62.
2. रिचड्र्स, एम., एवं हॉल, जे. (2023). जर्मनी के "ड्युअल सिस्टम" और उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भूमिका. European Journal of Vocational Training, 18 (2), 101–118.
3. वर्मा, कौशल. (2024). Role of skill development scheme in employment generation and economic development of Rajasthan- International Journal of Legal Research and Policy, 5(12), दिसम्बर 2024.
4. चौधरी, अरविंद. (2022). भारत में कौशल विकास और युवा रोजगार की चुनौतियाँ. Indian Journal of Economic studies, 14(2), 45–62
5. त्रिपाठी, अमिता. (2021). महिला सशक्तिकरण और कौशल प्रशिक्षण. Journal of Social Development, 19, 71–88.
6. जोशी, धर्मेन्द्र. (2021). कौशल विकास और ग्रामीण युवाओं का प्रवास. Indian Labour Journal, 63(3), 119–138.
7. साहू, दीपाली. (2020). "Study of corporate social responsibility towards enhancement of employment through skill development: An empirical study- International Journal of Reviews and Research in Social Science 8(1), 55–73.
8. अग्रवाल, मनीष. (2020). डिजिटल इंडिया और कौशल विकास का अंतर्संबंध. International Journal of Management and Economics, 12(4), 88–104.
9. राठौर, सीमा. (2020). कौशल विकास योजनाओं का सामाजिक प्रभाव. Journal of Rural Policy, 7, 99–117.
10. जिला सांख्यकी वार्षिक रिपोर्ट 2024–25.

❑❑❑